नयी राजनीतिक जमीन के लिए रणनीति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के चार राज्यों में होने वाले चुनावों की तैयारी का बिगुल फूंक दिया है। ब्रह्मपुत्र नदी पर देश के सबसे लंबे पुल के उद्घाटन के मौके पर क्षेत्र के विकास से जुड़ी कई योजनाओं का ऐलान करके जनता के लिए उन्होंने तरक्की का पैगाम जारी किया। उत्तर-पूर्व के सात में से तीन सूबों असम, मणिपुर और अरुणाचल में अपनी सरकारों के आसान गठन से भाजपा खासी उत्साहित है। अब वह नगालैंड, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा पर राज करने की तैयारी में जुटी है। इन राज्यों की नयी विधानसभाओं को आगामी वर्ष की शुरुआत में चुना जाएगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड आदि पांच राजयों में से चार में सरकारों के बन जाने के बाद भाजपा ने कामयाबी के नए लक्ष्य तय कर लिए हैं। प्रधानमंत्री गुजरात और हिमाचल प्रदेश, जहां चुनाव इसी साल होने हैं, में विजय अभियान का श्रीगणेश पहले ही कर चुके हैं। अब ब्रह्मपुत्र नदी के 9.15 किलोमीटर लंबे पुल को गायक भूपेन हजारिका की स्मृति को समर्पित कर प्रधानमंत्री ने स्थानीय जनता को क्षेत्रीय आकांक्षाओं से जोड़ने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा, जहां हिन्दू आबादी 80 प्रतिशत तक है, में जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है। अन्य राज्यों में भी उसे जीत का भरोसा है। लेकिन ये सभी ईसाई बहुल हैं। वैसे यह जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के करीब दर्जनभर संगठनों के हजारों कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर वर्षों से आदिवासियों और विभिन्न कबीलों में पैठ बनाने के लिए सांस्कृतिक व सामाजिक कामों में जुटे हुए हैं। इस सबके बीच केंद्र सरकार की नयी पशु क्रूरता निवारण नीति भाजपा की गंभीर चिंता का विषय जरूर बन गई है। जनता में नाराजगी को देखते हुए क्षेत्रीय नेताओं के इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया है। बहरहाल, नयी पशु नीति के बावजूद त्रिपुरा में भाजपा अब भी दौड़ में सबसे आगे है। एक ओर कांग्रेस तो दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस से बड़ी संख्या में नेता भाजपा में शामिल हुए हैं। राज्य में भाजपा की बढ़ती ताकत का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 2013 के विधानसभा चुनाव में उसे केवल 1.54 प्रतिशत वोट मिले थे, लेकिन 2016 में हुए बरजाला उपचुनाव में उसे मिलने वाले वोट 36 फीसदी तक पहुंच गए। इससे पहले 2015 में प्रतापगढ़ और सरमाह के उपचुनावों में सिर्फ 22 फीसदी मतदाताओं ने उसके पक्ष में मतदान किया था। हालांकि 2013 में माकपा ने 60 में से 51 सीटें जीती थीं, लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। माकपा के महासचिव बिजन धर भी स्वीकार करते हैं कि भाजपा ने मुख्य विपक्षी दल की हैसियत हासिल कर ली है। लेकिन इस राज्य की एक अहम बात आदिवासियों तथा बंगालियों के बीच लगातार टकराव भी है। सामुदायिक शत्रुता और हिन्दू आबादी का लगभग 80 प्रतिशत होना भाजपा अपने लिए अनुकूल मानती है। मेघालय में भाजपा ने अपनी कार्यसमिति में 16 में से 12 आदिवासी चेहरे शामिल किए हैं। केवल चार सदस्य हैं जो गैर आदिवासी हैं। लेकिन यहां पार्टी के क्षेत्रीय नेता बर्नार्ड मराक के नयी पशु नीति के विरोध में इस्तीफा देने से सारे जोश पर पानी फिर गया है। यह भाजपा की उम्मीदों पर ग्रहण का कारण इसलिए बन सकता है क्योंकि राज्य की करीब 30 लाख आबादी में ईसाई 80 और हिन्दू केवल 12 और मुस्लिम 4.50 फीसदी हैं। मिजोरम में भी ईसाई बहुलता में हैं। पांच बार मुख्यमंत्री रह चुके कांग्रेस के ललथनहवला का दावा है कि इस बार भी उनकी ही पार्टी सरकार बनाएगी। गोमांस का मुद्दा यहां भी भाजपा के लिए परेशानी की वजह बना हुआ है। नगालैंड न केवल ईसाई बहुल है, वरन यहां के लोग पड़ोसी सूबों के मुकाबले बीफ के और ज्यादा आदी हैं। यहां गैर-ईसाई आबादी लगभग 12 प्रतिशत है। भाजपा के लिए मतदाताओं में पैठ बनाने में जनसंख्या का यह अनुपात बाधा बना हुआ है। एक रणनीति के तहत पार्टी वहां की गैर-ईसाई समाजसेवी और स्वतंत्रता सेनानी रानी मां ग्वाडेंलू की ऐतिहासिक विरासत के सहारे रास्ता बनाने की कोशिश में है। बहरहाल, 60 सदस्यीय विधानसभा में पार्टी चार विधायकों के साथ नगा पीपुल्स फ्रंट की सरकार में शामिल है। पूर्वोत्तर के चुनावों का दूरगामी महत्व है। इस क्षेत्र से कुल 25 सांसद चुने जाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए न केवल लोकसभा बल्कि राज्यसभा में भी संख्या बल की दृष्टि से बहुत अहमियत रखते हैं। अभी तक पूर्वोत्तर राज्य दिल्ली सरकारों की अनदेखी और उपेक्षा का शिकार रहे हैं। यह पहली बार है कि प्रधानमंत्री ने पिछले तीन साल में वहां लगातार दौरे करके जनता का भरोसा हासिल किया है, साथ ही पूरे क्षेत्र को देश की मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश भी की है।

किसान की नियति सूखा, कर्ज और गोलियां

आजाद भारत की यह कितनी बड़ी विडंबना है कि जिन बहुसंख्यक किसानों, मजदूरों के वोट बैंक के आधार पर सरकारें बनती हैं और जिनके विकास के नाम पर लोकलुभावन योजनाएं लाई जाती हैं, वही तबका सबसे ज्यादा शोषित,उपेक्षित और दमित है। सत्ता में आने के बाद सत्ताधीशों की बदलती नीति, नीयत और निष्ठा इसकी सबसे बड़ी वजह है। अपने हक की आवाज बुलंद करने पर उसके हिस्से गेहूं और धान की लहलहाती बालियां नहीं बल्कि दनदनाती गोलियां आती हैं। अकाल, कर्ज और गोलियां भारतीय किसान की अब नियति हो गई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर दलौदा में आंदोलित किसानों पर सीआरपीएफ और पुलिस फायरिंग में छह और किसानों की मौत इस उपेक्षित वर्ग की इस दारुण व्यथा की दुखद परिणीति है। समझ में नहीं आता कि जनता द्वारा जनता के लिए चुनी गई जनता की सरकार जनता की पैरोकार है या फिर उद्योगपतियों पूंजीपतियों की हितैषी है। उसे हाड़तोड़ मेहनत करने के बाद भी दो जून की रोटी के लायक लागत नहीं निकलने वाले कर्ज में दबे करोड़ों किसानों के कर्ज को माफ करते तो खजाना खाली हो जाने की याद आती है मगर उद्योगपती व्यापारियों को करोड़ों करोड़ को माफ करते शर्म नहीं आती? यह जनतांत्रिक लोकतंत्र है या फिर लोकतांत्रिक पूंजीवाद है? मंदसौर के दलौदा में कर्ज में दबे किसान हफ्तेभर से आंदोलित थे। महीनों से वे अपनी पीड़ा नर्बदा मैंया के जयकारे में लगे आधुनिक भागीरथी मुख्य मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संज्ञान में ला रहे थे। मगर हमने नहीं देखा हमने नहीं सुना की तर्ज पर उनकी सरकार अंजान बनी रही। सीआरपीएफ और संवेदना खो चुकी सरकारी मिशनरी के भरोसे इस आंदोलन से निपटने का प्रयास किया जाता रहा है। उपेक्षा से किसानों का धैर्य चुकने लगा। सरकार के लोगों को ऐसे मामलों में अक्सर इसी अवसर का इंतजार होता है।

मुख्यमंत्री ने देर से दबाव में ऐन मौके पर उस समय मांगों को पूरा करने का आधा अधूरा ऐलान किया जब यह आंदोलन धीरज और नेतृत्व खो रहा था। गुस्साई उग्र भीड़ के ट्रकों में आग लगाने और रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाने तथा पथराव की प्रतिहिंसा में बतौर सुरक्षा सीआरपीएफ के गोलीचालन से छह किसानों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हैरत की बात है कि खून की होली खेलने के बाद भी सरकार फायरिंग से इंकार कर इसके लिए किसानों और असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार बता अपना दामन छुड़ाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस ने शिवराज सिंह की भाजपा सरकार को दमनकारी और किसान विरोधी बताते हुए गोली चालन के लिए जिम्मेदार लोगों पर हत्या का अभियोग दर्ज करने की मांग की है। भाजपा सरकार के साथ गोली कांड का चोली दामन का साथ रहा है। किसानों, मजदूरों, छात्रों और कर्मचारियों पर गोलीचालन सबसे ज्यादा भाजपा के कार्यकाल में ही हुआ। इंदौर, बैलाडीला, दल्ली राजहरा, भिलाई, बीएनसी मिल राजनांदगांव जैसे मजदूरों पर गोलीकांड हुए। सवाल इस बात का है चिलचिलाती धूप, मूसला धार बरसात और कड़ कड़ाती ठंड में कमरतोड़ मशक्कत कर देश का पेट भरने वाला किसान आखिर कब तक भूखा और नंगा रहेगा ? क्या उसके परिवार के लोगों को जीने लायक आय और सम्मान का जीवन जीने का अधिकार नहीं है? और अपनी मेहनत और उपज के एवज में आवाज उठाने पर उसे आखिर कब तक गोलियों से छलनी होना पड़ेगा। विदर्भ और बुंदेलखंड में सालों से सूखे के बाद भी सरकारों ने वहां के खुदकुशी करने वाले किसानों के लिए क्या किया । मध्यप्रदेश यूपी पंजाब हरियाणा छत्तीसगढ़ के किसानों की कमोबेश एक सी स्थिति है। पिछले 18 साल में कर्ज के चलते बैंकों से प्रताड़ित होकर तीन लाख से अधिक किसान खुदकुशी कर चुके हैं।

पी साईंनाथ के सुझावों को कांग्रेस और भाजपा सहित सभी सरकारों ने हवा में उड़ा दिया। आजादी के बाद कृषि और किसानों के विकास के लिए बने आयोग, कमेटियों की सिफारिशों को कितने प्रतिशत लागू किया गया? सच तो यह है कि परतंत्र भारत में प्रेमचंद के गोदान के होरी आज भी गरीबी और कर्ज से गांव गांव में उसी कीटनाशक दवा से खुदकुशी करने मजबूर हैं जिसे वे अपनी फसल को कीटमुक्त करने कर्ज लेकर लाए थे। वक्त के हिसाब से उनकी स्थिति में बदलाव नहीं आया है। सातवां वेतनमान लागू होने के बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का भी वेतन 25 हजार से ऊपर हो गया है। जबकि किसान की वार्षिक आय महज करीबन 18 हजार रुपए है। इसी में उसे अपने परिवार का खाना, पहनना, इलाज और शादी ब्याह के साथ कर्ज भी छुड़ाने का करिश्मा सरकार को दिखाना है। पूंजीपतियों और सत्ता में बैठे लोगों तथा एलीट क्लास के घरों की महिलाएं जिन कुत्तों को लेकर घूमती हैं उन टामियों के खर्च भी पचीस हजार से लाख रुपए महीना है। सरकार की शाईनिंग इंडिया से लेकर मेक इन इंडिया से भारत को अमेरिका बनाने की सनक इस देश के करोड़ों किसानों, मजदूरो,आदिवासियों दलितों और अल्पसंख्य जैसी मुफलिस जनता पर भारी पड़ रही है। छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश जैसे राज्यों में कृषि का रकबा उद्योगों, बिल्डरों और ब्यूरोक्रेट्स की भेंट चढ़ता जा रहा है। अकाल अंग्रेजों के समय भी पड़ते थे। अनावृष्टि और अति वृष्टि इंसान नहीं प्रकृति के हाथ में है। मगर जब मानसून कृषि के लिए जुआ बना हुआ है तो फिर सरकारें इसे देखते हुए कृषि के लिए बजट के साथ जमीनी योजनाएं क्यों नहीं बनातीं। यह बात आज तक किसानों ही नहीं बल्कि उसे जिताने वाली जनता को भी समझ नहीं आई समझ तो यह भी नहीं आ रहा है कि हर योजना की तरह किसान और कृषि की योजानाओं की राशि की बंटरबांट जब सरकार में बैठे राजनीतिक और सरकारी अमला करता रहेगा तो किसान कैसे संपन्न और सुखी रहेगा।

1975 में इंदिरा सरकार में चौधरी आयोग में सीमांत किसानों के मुकम्मल लागत के लिए खाद बीज, पानी, बिजली और मंडी तक की योजना बनी थी। मगर इसकी सिफारिशों को तीस दशकों तक सत्ता में रही कांग्रेस ने उसी तरह लागू करना मुनासिब नहीं समझा जिस तरह मोदी सरकार अपनी उद्योग परस्त नीति में किसानों को बिसराए हुए है।

गाय, चर्बी, मुसलमान, पाकिस्तान, राम मंदिर जैसे फिजूल के जुमलों में उलझी यह सरकार जनता के रोजी रोटी के अहम मसलों को झोड़कर भावनात्मक आधार पर अपना वोट बैंक पुख्ता करने में लगी हुई है। औसत आदमी को जानबूझकर इन मुद्दों में उलझाकर रखा गया है। दरअसल बात भाजपा की ही नहीं हर सत्ता का चरित्र ही एक जैसा होता है। सत्तर सालों में यदि तमाम सियासी दलों के चरित्र पर शोध किया जाए तो निष्कर्ष यही आएगा कि उन्होंने किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, स्त्रियों, दलितों, युवाओं के हितों के लिए अरबों की योजनाएं तो बहुत बनाईं मगर या तो इन पर अमल में ईमानदारी नहीं दिखाई या फिर इनका बजट हजम कर गए। तमाम घोटाले इसका प्रमाण हैं। इस हाईटैक दौर में अब सरकार को न सिर्फ संवेदनशील होने की जरुरत है बल्कि यह चिंतन करने की दरकार है कि आंदोलन के बाद ही मांगें क्यों पूरी होती हैं, पहले क्यों नहीं? क्या संबंधितों की कुर्बानी जरुरी है।

आखिर जनता और देश के प्रति प्रतिबद्धता की शपथ लेकर ही तो सरकार चुनी जाती और शपथ लेकर काम करती है। क्या सत्ताधीश और ब्यूरोक्रेट्स नैतिकता महज मंचों के लिए लिए बचा कर रखे हैं। कथनी और करनी में फर्क और कब तक करते रहेंगे। उन्हें आखिर किस जनता की किस घड़ी का इंतजार है?

'आंसू' महाकाव्य का पुनर्लेखन

आंसू की हर बूंद मोती है। जब वह छायावाद के अग्रसर कवि के हाथ लगा तो अमर काव्य बन गया और कृष्ण के वियोग में बहा तो उसने राजघराने की बहू को जोगन बना दिया। हालांकि मगर और घड़ियाल प्रजाति के जीव अपने अश्रु के माध्यम से भोजन के साथ ग्रहण कर लिए गए अतिरिक्त लवण का उत्सर्जन भर करते हैं, फिर भी वे हमें झूठी सहानुभूति प्राप्त करने या पश्चाताप करते दिखने की कला तो सिखा ही गए हैं। आंसू की बात चले तो हमारे जेहन में किसी ट्रेजिडी क्वीन या विरहिणी नायिका की तस्वीर उभरने लगती है। बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि औरत जब आंसू बहाने लगती है तो बहादुर से बहादुर मर्द अपनी तलवार म्यान में रख लेता है। यानी औरत के आंसुओं की मार तलवार की धार से भी ज्यादा तेज होती है। औरत के आंसुओं का महिमामंडन करते-करते हम भूल गए कि द्वारकाधीश ने अपने आंसुओं से ही बालसखा सुदामा के पैर धोए थे। अयोध्या पति दशरथ ने 'रघुकुल रीति' को निभाने के लिए रानी को दिए वचन का पालन करते हुए राम को वनवास तो दे दिया था मगर मृत्युपर्यंत उन्होंने पुत्र-वियोग में कितने आंसू बहाए, उसका उल्लेख कहीं नहीं मिलता। अब सर्वथा नयी जानकारी आई है कि मोर के आंसू बड़े 'वीर्यवान' होते हैं। मोरनी उसका भक्षण करने से प्रजनन प्रक्रिया में शामिल हो जाती है। मोर बिना ब्रह्मचर्य व्रत खंडित करे बाप बन जाता है। पक्षी विज्ञानी कहते हैं कि नर मोर अपने पंख फैलाकर शानदार नृत्य कर मादाओं को रिझाता है और 'एंटीरोमियो दल' का ख़तरा न होने से उनके साथ वही करता है जो कुदरत ने अधिकृत किया है। जब सूर्य के मंत्र के उच्चारण मात्र से कोई कुंआरी कन्या गर्भवती हो सकती है तो मोर के अश्रुओं का पान कर मोरनी क्यों नहीं हो सकती? नृत्य शायद इसलिए करना पड़ता हो कि उसका अश्रुपात इसके बिना होता ही नहीं हो। मनुष्यों में भी इसे संतानोत्पत्ति की एक अतिरिक्त विधि के रूप में मान्यता मिल जाए तो न सिर्फ़ एक नोबेल पुरस्कार हमारे देश में आ सकेगा बल्कि देश को कई समस्याओं से मुक्त भी किया जा सकेगा। जनसंख्या विस्फोट रोकने के लिए नसबंदी की तुलना में 'आंसूबंदी' एक आसान, कम खर्च वाला और ज्यादा अपनाए जाने वाला विकल्प साबित होगा। मां न बन पाने वाली स्त्री बांझपन के ताने सुनने से बचेगी। हां 'स्टेराइल' पुरुष को आंखों के 'सूखेपन' को लेकर ताने ज़रूर सुनने पड़ सकते हैं। महाकाव्य 'आंसू' के पुनर्लेखन पर भी विचार किया जा सकता है।

शिक्षा पर कदमताल

आजकल बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट चर्चा में हैं। सीबीएसई के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट, दोनों के परिणाम आ गए हैं और कुछ राज्यों के नतीजे भी निकले हैं। कुछ राज्य बोर्डों के नतीजे विवाद का विषय भी बन गए हैं, जिनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है। पिछले दो दशकों से जितनी उठापटक शिक्षा के क्षेत्र में होती आई है, उतनी शायद किसी और क्षेत्र में नहीं हुई। माध्यमिक स्तर पर तो क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, इम्तिहान कैसे लिया जाए, यही तय नहीं हो पा रहा है। केंद्र में जो भी सरकार आती है, वह इस पर अपने तरीके से प्रयोग करने लगती है। यूपीए सरकार ने 2010 में दसवीं का बोर्ड हटा दिया। यह कहकर कि कच्ची उम्र में बच्चों पर बहुत ज्यादा दबाव रहता है। लेकिन एक साल बाद उसी सरकार ने बोर्ड को स्वैच्छिक बनाकर वापस ला दिया। यानी कोई चाहे तो बोर्ड में बैठे, न चाहे न बैठे। अब सीबीएसई 2018 से दसवीं की बोर्ड परीक्षा को फिर से अनिवार्य करने जा रहा है। सरकार का तर्क है कि इससे गुणवत्ता वापस आएगी। गुणवत्ता कैसे आती है और यह असल में है क्या, यह हर गवर्नमेंट अपने-अपने तरीके से तय करती है।

राशिफल

मेष - आपका कार्य कौशल देखने लायक होगा। नई-नई योजनाओं के क्रियान्वन पर ध्यान केंद्रित रहेगा। बेहतर निवेश के लिए तुरंत कदम उठाएं।

वृष - आपकी ऊर्जा, करिश्मा, प्रभावशीलता इस समय शीर्ष स्तर पर बने हुए हैं। उदर विकार, पित्त विकार या ब्लड प्रेशर परेशान करेगा।

मिथुन - स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियों से जुझना पड़ेगा। निरंतर भागदौड़ की स्थितियां लगातार आयेंगी। आध्यात्मिक बने रहना आपके लिए लाभदायक रहेगा।

कर्क - आप ऊर्जा से भरे रहेंगे और कुछ नए कदम साहसिक कदम उठाएंगे। आपकी लोकप्रियता में वृद्धि होगी। आपकी लोकप्रियता से विरोधी पक्ष तिलमिला जाएगा।

सिंह - आप आत्म सुधार और विकास पर कुछ धन खर्च कर सकते हैं। जीवनसाथी से संबंधों में कटुता आएगी जिस कारण मन उद्वेलित रहेगा।

कन्या - इस समय मकान और जमीन के सौदों से भी अच्छे मुनाफे की संभावना दिखाई दे रही है। व्यवसाय हो या नौकरी दोनों ही क्षेत्र में उन्नति के द्वार खुलेंगे।

तुला - आप कामकाज को अत्यंत युक्ति संगत व सुचारु करेंगे। स्वास्थ्य में कष्ट प्रतीत होगा। कुछ सामाजिक या धार्मिक सेवा के कार्य भी किए जा सकते हैं।

वृश्चिक - घर, गृहस्थी, दाम्पत्य से संबंधित मामलों का तनाव भी ठीक होगा। नवीन कार्यों में मित्र वर्ग से वांछित सहयोग मिलेगा।

धनु - मानसिक तनाव भी कुछ कम होगा। संतान से संबंधित समस्याएं भी काफी कम हो जाएंगी। राजकीय कार्यों में लाभ होगा।

मकर - भाग्य और धर्म आदि बातों पर ध्यान संकेन्द्रित होगा। आजीविका के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। उत्तरार्द्ध में लोकप्रियता पुनः बुलन्दियों पर होगी।

कुंभ - खर्च के मुद्दों पर ध्यान संकेन्द्रण बनेगा। शीत प्रकृति के रोग, ज्वर आदि से पीड़ित होंगे। खान-पान की अनियमितता से बचना चाहिए।

मीन - भाई बहन बंधु बांधव से संबंधित मामले कुछ कमजोर बने रहेंगे। आजीविका क्षेत्र में परिवर्तन का भी मन बनेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से माह कष्टप्रद रहेगा।

शब्द सामर्थ्य

शब्द सामर्थ्य -076(Rns)

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं

1. भारत का एक पड़ोसी देश 4. जगन्नाथ, संसार के स्वामी, परमेश्वर 6. थामने की क्रिया, रोककर रखने की शक्ति 8. धनुष, सैन्य टुकड़ी 9. स्वदेश, मातृभूमि 10. माप, मापने की क्रिया 11. बगीचे की देख-रेख करने वाला, बागबान, माला बनाने व बेचने वाली एक जाति, आर्थिक 12. दानी होने का भाव 14. लाभ, फायदा 15. रक्त, लहू, वध 16. चालीस किलोग्राम की तौल, अंत:करण 17. सोचना, विचार करना 19. प्रतीति, विश्वास 20. टकराव, मुड़भेड़ 21. पांच से छोटी एक विषम संख्या 22. नर्म, मुलायम।

ऊपर से नीचे

1. रंगमंच के पर्दे के पीछे की जगह, वेशभूषा, रंगशाला 2. पवित्र, निर्मल, भोजन पकाने की क्रिया, रसोई 3. बाल्यावस्था, लड़कों सा आचार व्यवहार 4. संसार, दुनिया, जगत 5. हिन्दुओं का सबसे बड़ा त्यौहार 7. तुरत-फुरत, बात की बात में, तुरंत 10. अबोध, मूर्ख 11. मां, जननी 13. सूनसान, उजाड़, जनहीन 14. खारा, नमक के स्वाद जैसा 15. शुष्क हृदय, मूर्ख 17. मृत्यु को प्राप्त होना 18. नया, नव 19. अनाथ, बेसहारा।

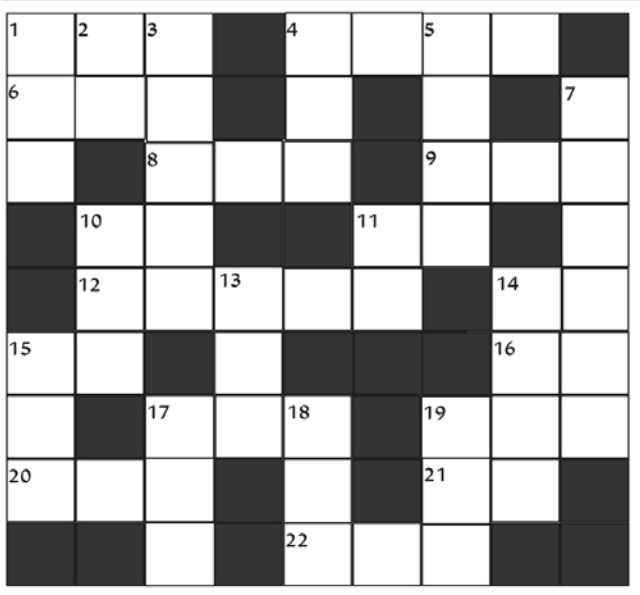

पिछले अंक का हल

मु	हा	व	रा		त	क	ली	फ
ज		र	ज	नी	श		प	ल
रा	व	ण			री	झ	ना	
	ह			स	फ	र		न
	म	हा	रा	जा		ना	य	क
वि		र		या	न			च
प्र	भु		को	फ्ता			क	ढ़ा
	जं				प्या		य	
अ	ग	र	म	ग	र	क	र	ना

सू-दोकू

	9		1	6		2		7
3								
		6					9	
7			5		1		3	
	8			9		6		2
		4					7	
	3				2	9		6
6		7	3					4
	4			1		7	8	

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गो का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक भर सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

पिछले अंक का हल

2	6	3	9	8	7	1	5	4
8	5	1	3	2	4	6	7	9
9	4	7	1	5	6	8	2	3
3	9	8	6	7	1	5	4	2
6	1	2	5	4	3	9	8	7
5	7	4	8	9	2	3	1	6
1	2	6	7	3	5	4	9	8
4	8	5	2	6	9	7	3	1
7	3	9	4	1	8	2	6	5